राजस्थान में 9763 नये आवासों को केन्द्र सरकार की मंजूरी मिली

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत मिली है स्वीकृति

जयपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबको पक्का मकान उपलब्ध कराने के विजन को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने 9 हजार 763 नये आवासों को केंद्र सरकार से स्वीकृति के लिए मंजूरी प्रदान की है। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत राजस्थान को आज बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है।

मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी (एसएलएसएमसी) की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इन आवासों के लिए प्रत्येक पात्र लाभार्थी को कुल 2.50 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा, जिसमें 1.50 लाख रुपए केन्द्र सरकार और एक लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से प्रदान किया जायेगा। इस निर्णय से कुल 244.07 करोड़ रुपए की सब्सिडी पात्र परिवारों को उपलब्ध होगी।

मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई।

इन आवासों की अंतिम स्वीकृति केन्द्र सरकार की 17 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली सीएसएमसी की बैठक में प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में किये जा रहे प्रयास न केवल शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगे बल्कि उन्हें गरिमामय जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेंगे।

- इन आवासों के लिए प्रत्येक पात्र लाभार्थी को कुल 2.50 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा, जिसमें 1.50 लाख रुपए केन्द्र सरकार और 1 लाख रुपए राज्य सरकार देगी

बैठक में प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग डॉ. देबाशीष पृष्टि, शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग नवीन जैन, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग रवि जैन सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

आर्मी से रिटायर्ड जवान ने दुनाली बंदूक से की आत्महत्या

मृतक एक निजी कंपनी में गार्ड पर कार्यरत था, पुलिस और एफ.एस.एल. टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए

जयपुर। सोडाला थाना इलाके में आर्मी से रिटायर्ड जवान ने लाइसेंसी बंदूक से पेट में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जो एक निजी कंपनी में गार्ड पर कार्यरत था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल स्थाल साक्ष्य जुटाए। पुलिस की प्रारंभिक जांच में किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।

थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि थाना इलाके के हटवाड़ा के लक्ष्मीनगर निवासी भुवनेश जाट (40) आत्महत्या की है,जो मूलत: हिंडौन के बड़खेड़ा के रहने वाले था। भुवनेश जाट आर्मी से रिटायर हुए थे और पत्नी और बेटे के साथ लक्ष्मीनगर में किराए के मकान में कुछ दिन पहले ही रहने आए थे। भुवनेश जाट सी-स्कीम स्थित गोल्ड कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था।

थानाधिकारी ने बताया कि भुवनेश जाट की पत्नी शुक्रवार सुबह किसी काम से बाहर गई थी और उसका बेटा कंप्यूटर क्लास में गया था। इस दौरान भुवनेश जाट घर पर अकेले था।

जिन्होंने कमरा अंदर से बंद कर लिया। खुद की लाइसेंसी बंदूक से पेट में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बंद कमरे से अचानक धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। पड़ोसियों ने कमरे के अंदर जाकर देखने की कोशिश की। लेकिन कमरे के आगे-पीछे के दोनों गेट बंद मिले।

कुछ ही देर में उनकी पत्नी और बेटा भी घर आ गए। अनहोनी की आशंका के चलते तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने धक्का देकर गेट खोला। जहां भुवनेश का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके पेट में गोली लगी हुई थी। उसकी लाइसेंसी बंदूक पास ही बेड पर पड़ी थी। पुलिस ने तुरंत एफएसएल टीम को बुलाकर मौके से सबूत जुटाए। पुलिस की प्रथमदृष्टया जांच में सामने आया है कि भुवनेश ने बिस्तर पर एक पैर रखकर अपनी लाइसेंसी बंदूक को पेट पर लगाया।

बंदूक का ट्रिगर दबाते ही गोली पेट में लगने से वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने सबूत जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया है। पुलिस के अनुसार किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर गांव-गांव में पहुंचेगी सरकारी सेवाएं

राजस्थान में 17 सितंबर से शुरू होगा ''ग्रामीण सेवा शिविर'' अभियान

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीण जनता को राहत पहुंचाने और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने के उद्देश्य से 17 सितंबर से प्रदेशभर में 'ग्रामीण सेवा शिविर' अभियान शुरू करने जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरणबद्ध रूप से शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आमजन के कार्य मौके पर ही निस्तारित किए जाएंगे। यह विशेष अभियान सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित होगा। अभियान के पहले सप्ताह में बुधवार को भी शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र की दो ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन शिविर होंगे और तब तक जारी रहेंगे जब तक उस क्षेत्र की सभी पंचायतों को शामिल नहीं कर लिया जाता।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अभियान को राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को जनता के और करीब लाने वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीणों को अपने जरूरी कामों के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें सरकारी सेवाएं उनके गांव में ही उपलब्ध होंगी। राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि शिविरों के आयोजन, निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी जिला कलक्टरों को सौंपी गई है। प्रत्येक शिविर के लिए प्रभारी और सहायक प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, और संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इन शिविरों में राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय, कृषि, पशुपालन, बिजली, पंचायत राज आदि विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। प्रमुख कार्यों में नामांतरण, सीमांकन, रास्ते खोलने, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करना, आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं, पशु स्वास्थ्य शिविर, स्कूलों की मरम्मत हेतु स्वीकृति, किसान रजिस्ट्री से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण, बीज मिनी किट वितरण, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, बिजली सुधार कार्य, जनहानि, पशुहानि एवं मकान क्षित के प्रकरणों की जांच और स्वीकृति शामिल हैं। इसके साथ ही 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले सहकार सदस्यता अभियान को भी ग्रामीण सेवा शिविरों के साथ जोड़ा जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत सहकारी समितियों में सदस्यता बढ़ाने और सहकारिता के माध्यम से गांवों को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया जाएगा। सरकार की मंशा है कि जो भी ग्रामीण इन शिविरों में आए, उनका कार्य प्राथमिकता से उसी दिन पूरा किया जाए। यदि किसी कारणवश कोई कार्य उसी दिन संभव न हो, तो उसकी विभागवार सूची बनाकर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने अपील की है कि ग्रामीणजन इन शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और सरकार की योजनाओं व सेवाओं का लाभ उठाएं। यह अभियान शासन और जनता के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

पशुपालन विभाग के 231 अधिकारी पदोन्नत

जयपुर । पशुपालन विभाग के राजस्थान राज्य पशुपालन सेवा संवर्ग के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा अतिरिक्त निदेशक तथा निदेशक स्तर के विभिन्न संवर्गों के कुल 231 पदों के लिए शुक्रवार को शासन सचिवालय में पदोन्नित समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य प्रो. अयूब खान ने की। बैठक में शासन उप सचिव संतोष करोल, दिनेश कुमार शर्मा, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग एवं पशुपालन विभाग के कार्यकारी निदेशक डॉ आनंद सेजवा भी उपस्थित थे। बैठक में विभाग के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के दोनों पदों तथा अतिरिक्त निदेशक पद पर नौ अधिकारियों को पदोन्नत किया गया। इनके अलावा सामान्य तथा विशिष्ट अनुभाग के 51 अधिकारियों को संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नित दी गई। उपनिदेशक के पद पर 74 अधिकारियों तथा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर 95 पशु चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नित हुई है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया जयपुर फुट की शाखा का उद्घाटन

जयपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री विष्णूदेव साय ने जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस.एस.) के देश की 36वीं स्थायी शाखा का बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर के उद्घाटन किया । यह शाखा देश के सबसे खतरनाक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थापित की गई।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्य मंत्री विजय शर्मा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, वाणिज्य मंत्री लखन लाल देवांगन, बस्तर से सांसद महेश कश्यप, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष्य किरण देव सिंह, चित्रकूट विद्यायक विनायक गोयल, महापौर संजय पाण्डे, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस.एस.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मेहता, बी.एम.वी.एस.एस. के छत्तीसगढ के अध्यक्ष मदन लाल पारख बस्तर जिला कलेक्टर एवं एस. हरीश, जिला प चायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतीक जैन और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे । बी.एम.वी.एस.एस. के अध्यक्ष सतीश मेहता न बताया कि मुख्यमंत्री ने जयपुर फुट की निर्माण विधि देखी और विकलांगों को स्वयं जयपुर फुट पहनाकर उन्हें चलवाया । मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को ट्राईसाईकिल और अन्य उपकरण नि:शुल्क वितरित किए । बी.एम.वी.एस.एस. के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता ने बताया कि विगत वर्षों में नक्सल प्रभावित क्षेत्र विशेष रूप से सुखमा, दांतेवाडा, नारायणपुर में 12 विशेष शिविर लगाकर 4000 विकलांगों को लाभान्वित किया । इन क्षेत्रों में जाकर शिविर लगाना जोखिम भरा कार्य होता हैं, लेकिन इन प्रभावित क्षेत्रों में बी.एम.वी.एस.एस. ने शांतिपूर्ण वातावरण में नक्सपंथियों का विश्वास जीतकर शिविरों का सफल आयोजन कर लगभग 5000 विकलांगों को लाभान्वित किया। ऐसे उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में जाकर नि:शुल्क कृत्रिम अंग और अन्य उपकरणों का नि:शुल्क वितरण कर बी.एम.वी.एस.एस. और छत्तीसगढ प्रशासन ने आदिवासी क्षेत्र में सदभावना प्राप्त की । जिसकी सर्वत्र प्रशंसा मिली ।

छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में जयपुर फुट की स्थायी शाखा का उद्घाटन करने के बाद इसके निर्माण की विधि देखी।

तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज, राजीनामे से निपटेंगे लाखों मुकदमें

जयपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अदालतों के अलावा प्रशासनिक अधिकरणों, आयोगों और रेवेन्यू कोर्ट में भी लोक अदालत के तहत राजीनामे से मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में प्रकरणों की सुनवाई ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से होगी। जयपुर पीठ में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ सुबह 10 बजे प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा करेंगे। वहीं जोधपुर स्थित मुख्यपीठ में लोक अदालत का शुभारंभ हाईकोर्ट की विधिक सेवा समिति, जोधपुर के अध्यक्ष जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी करेंगे। प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्रि ने बताया कि निचली कोर्ट में केसों की सुनवाई के लिए 498 बेंचों का गठन किया है।

गरीब और वंचित वर्ग के युवाओं को मिलेगा नि:शुल्क कोचिंग का लाभ

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 14 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर की गई है

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति नि:शुल्क कोचिंग योजना अब और अधिक युवाओं के लिए अवसर लेकर आई है। सरकार ने इस योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 14 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें।इस वर्ष योजना के अंतर्गत 30 हजार विद्यार्थियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, यूपीएससी, आरएएस, पटवारी, रीट, पुलिस, बैंकिंग, एसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नि:शुल्क कोचिंग संस्थानों के माध्यम से करवाई जाएगी।

- इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, यूपीएससी, आरएएस, पटवारी, रीट, पुलिस, बैंकिंग, मेडिकल, एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जायेगी

योजना का उद्देश्य गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रभावी तैयारी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और दिव्यांगजन वर्ग के पात्र युवा एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और योजना में समय रहते आवेदन करें।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विद्यार्थियों को देश और राज्य की प्रमुख प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग दी जाती है।

इसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट, सीए, सीएस, सीएमए जैसी प्रोफेशनल प्रवेश परीक्षाओं के साथ-साथ यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा व सीडीएस, आरपीएससी की आरएएस व सब इंस्पेक्टर परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा आयोजित पटवारी व कनिष्ठ सहायक परीक्षा, एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रीट व कांस्टेबल जैसी भर्तियों की तैयारी शामिल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि कोई भी होनहार युवा संसाधनों के अभाव में पीछे न रह जाए।

यह योजना प्रदेश के हजारों युवाओं के सपनों को नई दिशा देने का कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने सभी पात्र युवाओं से योजना में आवेदन करने की अपील की है, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण कोचिंग का लाभ मिल सके और वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर आत्मनिर्भर बन सकें।

राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 10 हजार पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 13 और 14 सितम्बर को आयोजित की जाएगी। शुक्रवार देर शाम को जयपुर जंक्शन और सिंधी कैंप बस स्टैण्ड के आस-पास हजारों युवाओं की भीड़ उमड़ पडी, कुछ युवाओं ने रात में यहीं पर शरण ली।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने त्रिवेणी धाम पहुंचकर लिया साधु-संतों का आशीर्वाद

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंदिर में श्री सीताराम जी के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को शाहपुरा स्थित पावन त्रिवेणी धाम पहुंचकर संत अमृत समागम महोत्सव में भाग लिया।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को शाहपुरा स्थित पावन त्रिवेणी धाम पहुंचकर संत अमृत समागम महोत्सव में भाग लिया। यह आयोजन श्री भगवानदास महाराज के जन्मोत्सव और ब्रह्मलीन पद्मश्री संत नारायणदास महाराज के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।

दो दिवसीय इस धार्मिक महोत्सव में देशभर से साधु-संतों का समागम हुआ और त्रिवेणी धाम भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहा। दिया कुमारी ने त्रिवेणी धाम में श्री सीताराम जी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और उपस्थित साधु-संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने राम रिछपाल दास महाराज से भी विशेष रूप से आशीर्वाद लेकर आयोजन की महत्ता को रेखांकित किया।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में अध्यात्म, संस्कार और संस्कृति की जड़ों को गहरा करते हैं। त्रिवेणी धाम आकर सदैव एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है, जो जनमानस के लिए प्रेरणास्त्रोत है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए सभी वर्गों को मिलकर कार्य करना होगा। गुरुकुलों के माध्यम से यदि नई पीढ़ी को शिक्षा मिले तो वह सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में सशक्त भूमिका निभा सकती है।

- धार्मिक आयोजनों से समाज में संस्कार और अध्यात्म की जड़ें होती हैं मजबूत : दिया कुमारी

दिया कुमारी ने साधु-संतों के मार्गदर्शन को समाज के लिए अनमोल बताते हुए कहा कि उनका सान्निध्य जीवन में सकारात्मकता और संतुलन लाता है।महोत्सव में प्रवचन, धार्मिक अनुष्ठान और श्रीमद् भागवत कथा जैसे आयोजन हुए, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्ति और आध्यात्मिकता से भर गया। शनिवार को कथा का विधिवत समापन किया जाएगा। इस अवसर पर देवायुष सिंह शाहपुरा सहित अनेक श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक भी उपस्थित रहे।

नई अफीम नीति से हजारों किसानों को मिलेगा लाभ

जयपुर/नई दिल्ली। भारत सरकार ने अफीम खेती के लिए वर्ष 2025-26 की नई नीति जारी कर दी है, जिससे हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। यह नीति किसानों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है और इसमें कई नई श्रेणियों के किसानों को पात्रता दी गई है। नई नीति के तहत लेसिंग पद्धित और सीपीएस पद्धित दोनों में पात्र किसानों को क्रमश: 0.10 और 0.05 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की अनुमति दी जाएगी। पात्रता सूची सीबीएन की वेबसाइट पर जारी की जाएगी और किसानों को मोबाइल व ईमेल से सूचना दी जाएगी। चित्तौड़गढ सांसद सी.पी. जोशी ने इस नीति को किसानों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्रालय का आभार जताया।

निजता के हनन के आरोप बेबुनियाद, कांग्रेस खुद कर चुकी है फोन रिकॉर्डिंग : गोदारा

जयपुर । राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विपक्ष द्वारा लगाए गए निजता के हनन के आरोपों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पारदर्शिता और जनहित के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है, लेकिन विपक्ष बेवजह मुद्दा बनाकर राजनीति करने में जुटा है। मंत्री गोदारा ने कहा कि जब विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कोई ठोस बात नहीं होती, तो वे ऐसे झूठे आरोप लगाते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि पिछली सरकार में तो खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा फोन रिकॉर्डिंग करवाई गई थी।

ARYA COLLEGE OF ENGINEERING & I.T.
(An Autonomous Institute Affiliated by RTU & Approved by AICTE) www.aryacollege.in
Admission Under Management Quota / Direct Admission
APPLY FOR ADMISSION (SESSION 2025-26)
B.Tech. - I Year (REAP) | B.Tech. - II Year (LEEP) | MBA (RMAP) | M.Tech. (CAM)
LAST DATE: 13th SEPTEMBER, 2025
B.Tech Branches : ME • EE • ECE • CSE • IT • AI&DS
M.Tech Branches : CSE • Digital Communication • Power Systems
REAP CODE - 1014 | LEEP CODE - 1014 | RMAP CODE - 212
Contact : 9314881683, 9829017324
SP-42, RIICO Industrial Area, Delhi Road, Kukas, Jaipur - 302028